(b) the sector in which imports have increased?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Export performance during the current year is satisfactory with growth rate of 26.4% in $ terms during April-September 1995 compared to a lower growth of 12.3% during the corresponding period last year. Further, export growth is noted in most of the product groups. However, as per the latest available disaggregated trade data which relate to April-September 1995, a few items, namely, tobacco manufactured, oil meals, marine products, natural silk textiles, carpets and project goods show a decline in on low growth.

(b) The principal commodities in respect of which imports registered increase during April-September 1995 comprise edible oil; fertilizers; non-ferrous metals; machinery; pearls; precious, semi-precious stones; newsprint; synthetic & regenerated fibre; electronic goods; organic & inorganic chemicals; paper board & manufactures; project goods; professional instruments and manufacture of metal.

राज्य व्यापार निगम का निजीकरण

2113. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या सरकार राज्य व्यापार निगम का निजीकरण करने का विचार रखती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं और किन कारणों से निजीकरण किया जा रहा हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव पर निजी क्षेत्र की क्या प्रतिक्रिया हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग): सरकार ने राज्य व्यापार निगम का निजीकरण करने के विषय में कोई निर्णय नहीं लिया हैं।

विभिन्न वस्तुओं का आयात निर्यात

2114. **श्रीमती मालती शर्मा :**

श्री राजनाथ सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान भारत द्वारा अन्य देशों को किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया गया एवं देश वार किन-किन वस्तुओं का आयात किया गया; और

(ख) अगले तीन वर्षो के लिए सरकार ने आयात/निर्यात के लिए लक्ष्य निर्धारित किये हैं एवं निदेंशों को निर्यात करने के कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) मांगी गयी सूचना बहुत बड़ी हैं। ये आंकड़े डी जी सी आई एण्ड एस, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित "भारतीय विदेश व्यापार आंकड़े" (प्रमुख वस्तुएं एवं देश) से प्राप्त किए जा सकते हैं। नवीनतम अंक सितम्बर, 1995 का हैं जिसमें वर्ष 1995-96 के दौरान अप्रैल-सितम्बर, 1995 की अवधि के आंकड़े उपलब्ध हैं। मार्च, 1993-94 और मार्च 1995 के अंकों में क्रमश: वर्ष 1993-94 और वर्ष 1994-95 के ब्यौरे दिए गए हैं। इन प्रकाशनों की प्रतियां रसद पुस्तकालय जो कि डाक सूची में हैं, में उपलब्ध कराई गई हैं।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेश व्यापार कार्य-योजना का प्रमुख तत्व-निर्यात को बढ़ाना हैं। निर्यात वर्ष 1991-92 के मूल्यों एवं योजना अवधि (1992—97) के दौरान विनिमय दर पर अधिक मात्रा में 13.61 प्रति वर्ष की दर से वृद्वि होने का अनुमान हैं। निर्यात लक्ष्य व्यापारी वर्ग, उद्योग और अन्य संबंधित संस्थानों के परामर्श से इस मंत्रालय द्वारा वार्षिक आधार पर तय किया जाता हैं। चालू वर्ष (1995-96) में यू एस डालर के रूप में 20% की वृद्वि दर पर निर्यात लक्ष्य दशाया गया हैं। आयात की विशेष जरूरतों खासकर आठवीं योजना के दौरान 1.5 जीडीपी लोच और बड़ी मात्रा में वस्तुओं के आयात की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 8.4% प्रतिवर्ष आयात वृद्वि दर का अनुमान लगाया गया हैं। आयात जरूरतों के अनुसार किया जाता हैं, इसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। अप्रैल – अक्तूबर 1995 वह नवीनतम अवधि हैं जिसके संबंध में चालू वर्ष में विदेश व्यापार के आंकड़े उपलब्ध हैं, वास्तविक निर्यात पिछले वर्ष इसी अवधि के

दौरान हुए 13820 मिलियन यू एस डालर के निर्यात की तुलना में 17204 मिलियन यू एस डालर मूल्य का हुआ जिससे 24.5% की वृद्वि दिखाई पड़ती है। समग्र आर्थिक प्रगति के लिए विदेशी क्षेत्र निर्णायक होने के नाते सरकार का भविष्य में भी निर्यात में उच्च वृद्वि दर बनाए रखने का लक्ष्य हैं।

Imbalance in Payments for sugarcane by sugar mills

2115. SHRI BHUPNIDER SINGH MANN : Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) the number and names of sugar mills which pay least for the sugarcane they purchase and also that of sugar mills which pay higher sugarcane prices;

(b) the reasons for such imbalance in payments and steps contemplated to correct this trend in prices; and

(c) how many sugar mills are considered inefficient, their list, State-wise and steps being taken to make them efficient?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) It is obligatory on the part of every sugar factory in the country to pay the minimum price for sugarcane fixed by the Central Government as per Clause 3 of the Sugarcane (Control) Order, 1966 which was issued under the Essential Commodities Act 1955. However, State Government ask factories to pay cane prices higher than the Statutory Minimum Price. A statement showing ranges of sugarcane price actually paid by sugar mills in different States is enclosed (*See* below).

(b) Statutory Minimum Price (SMP) for sugarcane fixed by the Central Government is linked to a basic recovery of 8.5% with proportionate premium of 0.1% increase in recovery above the basic level. As such, the SMP of all sugar factories may not be the same.

(c) Ministry of Food does not maintain a list of inefficient units. However, the inefficiency may be due to variety of factors, such as inadequate cane avilability, un-economic size, old and obsolete plant and machinery, technical and managerial problems, under utilisation of capacity, etc. Ministry of Food is providing financial assistance at concessional rate of interest from the Sugar Development Fund (SDF) to the sugar mills for cane development and rehabilitation/ modernisation, subject to their fulfilling the prescribed conditions.

Statement

Rate at which cane price was paid by sugar mills in various states for the season 1994-95

State	Rate (Rs/Qts.)
(1)	(2)
Uttar Pradesh	66.00
Bihar	to 70.00 66.00 to 70.00
Punjab	68.00 to 72.00
Haryana	66.00 to 70.00
Assam	46.00 to 53.00
West Bengal	58.00
Orissa	44.16 to 60.00
Madhya Pradesh	66.00 to 72.00
Rajasthan	57.00 to 66.00
Maharashtra	46.00 to 66.00